ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 184-187
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्रणाली में परीक्षा प्रणाली की प्रमुख समस्याओं का अनुशीलन

1. डॉ0 मायाशंकर, 2. डॉ0 भूपाल सिंह
1. एसोसिएट प्रोफेसर बी. एड विभाग, एम.डी.पी.जी कॉलेज, 2. असिस्टेंट प्रोफेसर , बी. एड. विभाग, प्रताप बहादुर पी0जी0 कॉलेज, सिटी, प्रतापगढ़ (उ0प्र0), भारत

भारतीय शिक्षा प्रणाली इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचनाओं के अनुरूप व्यवस्थित नहीं हुई थी। यह अंग्रेजी शासन पद्धति की आवश्यकताओं एवं उनके अनुरूप आचार–व्यवहार की मनोवृत्ति विकसित करने वाली विश्वविद्यालयीय शिक्षा प्रणाली के रूप में प्रारम्भ हुई थी। स्वाधीनता के बाद भी इस विचारधारा का पोषण होता रहा तथा संसाधनों के अभाव, नीतियों की कमी एवं शासन तंत्र की उपेक्षा के कारण उसी शिक्षा व्यवस्था को अनवरत आगे अग्रसारित किया गया जिसके कारण यह भारतीय एवं भारतीयता की विचारधारा से दूर ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि देश की शिक्षा प्रणाली देश के आम जनमानस के साथ पूर्णतया नहीं जुड़ पायी। अंग्रेजी माध्यम एवं अंग्रेजी भाषा लोगों के मन, मस्तिष्क को इतना प्रभावित की जिससे वे भारतीय भाषा हिन्दी एवं मातृभाषाओं के अध्ययन को उपेक्षित करने लगे। उच्च शिक्षा के लिए भारत में संचालित होने वाले विश्वविद्यालयों से भी आपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया क्योंकि इससे उनमें मौलिक चिन्तन एवं पूर्ण अभिव्यक्ति की कमी आने लगी। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषायी, विद्यालयी स्तर एवं अनेक चुनौतियों के कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली संकटग्रस्त एवं उपेक्षित प्रतीत होती है।

वर्तमान में उच्च अध्ययन एवं तकनीकि ज्ञान हेतु प्रतिभाओं का पलायन होता है, लोगों को भारतीय शिक्षा एवं ज्ञान पर सन्देह रहता है। यहॉं से उच्च बौद्धित स्तर वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विदेशों में पलायन हो जाता है जिससे उनका योगदान देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में नहीं हो पाता है। वर्तमान की अनेक चुनौतियॉं वर्तमान विश्वविद्यालयीय परीक्षा प्रणाली के मार्ग में बाधक बनी हुई हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली की विभिन्न समस्याओं का अनुशीलन प्रस्तुत शोध प्रपत्र में किया गया है।

विश्वविद्यालयीय परीक्षा प्रणाली की समस्याऍं :

विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली उचित नीति एवं नियति दोनों का शिकार हुई है। शिक्षा में किये जा रहे विभिन्न प्रयास अनमने एवं अनैच्छिक रूप से किये जाने के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे इसके अतिरिक्त शिक्षा की आन्तरिक एवं बाह्य कमियॉं इस मार्ग में विशेष बाधा उत्पन्न कर रही हैं। विश्वविद्यालीय परीक्षा की समस्याऍं निम्नवत हैं–

1. उचित शिक्षा नीति का अभाव– शिक्षा नीति वस्तुतः सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली तथा उसमें लाने वाले परिवर्तन की सूचक होती है। इसलिए एक अच्छी विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली में निम्न विशेषताऍं होनी चाहिए–

– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली का आधार नागरिकों की मातृभाषा तथा राष्ट्र भाषा होना चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली का सम्बन्ध आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से होना चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली अपने आप में व्यावहारिक व कार्यपरक होनी चाहिए।
– राष्ट्रीय शिक्षानीति विकासात्मक, सृजनात्मक तथा उत्पादक होनी चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली राष्ट्रीय एकता व सौहार्द को सुदृढ़ करने में समर्थ होनी चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का विकास करने में समर्थ होनी चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली छात्रों में व्यापक, वैश्विक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में समर्थ होनी चाहिए।
– विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक आधार पर विद्यमान शैक्षिक विषमताओं को दूर करने वाली होनी चाहिए।

2. परीक्षा में समन्वयात्मक नियन्त्रण की कमी– परीक्षा एक समन्वयात्मक प्रक्रिया है इसलिए शैक्षिक नियंत्रण में भी समन्वय की आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्ति, समाज, राज्य एवं राष्ट्र की सर्वोत्कृष्टता का परिचायक होती है अतः इस पर इनका नियंत्रण आवश्यक होता है। शिक्षा पर नियंत्रण से आशय शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये इससे सम्बन्धित पक्षों को अपने अभिमत एवं सुझाव का अधिकार दिया जाना अपेक्षित होता है। शिक्षा नीति एवं इसके विभिन्न पक्षों के लिये राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति एवं शिक्षा से जुड़े छात्र, अभिभावक, प्रशासक, शिक्षक एवं नीति निर्माताओं को

अनुरूपी लेखक

मिलकर इसके लिये नियोजन किया जाना चाहिए किन्तु वर्तमान में यह अधिनायकवादी स्थिति में है। शिक्षा की कोई भी व्यवस्था छात्रों, अभिभावकों पर जबरन डाल दी जाती है उन्हें जिन विषयों एवं बिन्दुओं पर कोई रूचि नहीं होती उसे भी उन्हें पढ़ने और अनुपालन करने के लिये बाध्य किया जाता है जिससे उनकी रूचि दिन ब दिन कम होती चली जाती है। परिणाम स्वरूप देश की छात्र संख्या का एक बड़ा भाग ड्राप आउट का शिकार हो जाता है।

3. शैक्षणिक अवसरों में समानता की समस्या– स्वाधीनता के पश्चात् विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी इन्हें सामान्य शिक्षा की स्थिति में नहीं लाया जा सका है जिसके अनेक कारण हैं। इनमें मुख्य कारण निम्नवत हैं–

(क) परीक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता– जिन स्थानों पर कोई भी उच्च परीक्षा संस्था नहीं है वहॉ के बच्चे शिक्षा प्राप्ति के वे अवसर प्राप्त नहीं कर पाते जो शिक्षा संस्थाओं से युक्त बस्तियों में रहने वाले बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। जब बच्चों के लिए सरलतासे तय करने योग्य दूरी पर शिक्षा संस्था की व्यवस्था नहीं होती है तो बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यहॉ यह भी इंगित करना उचित ही होगा कि देश के विभिन्न जनपदों में हो रहे शैक्षिक विकास में पर्याप्त अन्तर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

(ख) निर्धनता– निर्धनता शैक्षिक अवसरों में विषमता का एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारे देश की जनसंख्या का अधिसंख्य भाग गरीबी व निर्धनता से त्रस्त है, जबकि एक छोटा सा भाग आर्थिक रूप से साधन सम्पन्न है। निर्धन परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के वे अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते जो समृद्ध परिवारों के बच्चों को हो जाते हैं। शिक्षा शुल्क, पठन–पाठन सामग्री, विद्यालयी गणवेश, पौष्टिक आहार आदि की कमी के कारण निर्धन बालक या तो विद्यालय पहुॅच ही नहीं पाते हैं और यदि पहुॅच भी जाते हैं तो उनमें से अधिकांश शिक्षा बिना पूरी किये ही विद्यालय छोड़ देते हैं। कुछ शिक्षा स्तर पर तो स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है।

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में अन्तर– शैक्षिक विषमता के लिए विभिन्न स्कूलों, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में विद्यमान अन्तर भी उत्तरदयी है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अल्पसाधन युक्त स्कूल के छात्र को उपलब्ध शिक्षा तथा नगरीय क्षेत्र में स्थित साधन–सम्पन्न विद्यालय के छात्र को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता कभी भी समतुल्य नहीं हो सकती। यही कारण है कि जनपरीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता की तुलना करना कदापि तर्कसंगत नहीं हो सकता।

(घ) परिवार का वातावरण– परिवार के वातावरण का अन्तर शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में विषमता उत्पन्न करता है। अशिक्षित माता–पिता के बच्चे अथवा ग्रामीण परिवेश में रहने वाले माता–पिता के बच्चे शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो शिक्षित माता–पिता अथवा शहरी परिवार अथवा समृद्ध परिवार के बच्चे प्राप्त कर लेते हैं। अनपढ़ माता–पिता के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन/सहयोग नहीं मिल पाता है।

(ड.) यौन भेद– भारतीय परिवेश में लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा के बीच एक भारी अन्तर पाया जाता है। परम्परागत भारतीय समाज में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को हेय दृष्टि से देखा जाता है। लड़कियों की शिक्षा के प्रति इस नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण लड़के तथा लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

(च) सामाजिक स्थिति– समाज के प्रगतिशील तथा पिछड़े वर्गो के मध्य शैक्षिक विकास में अन्तर पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक विसंगतियों के कारण अनुसूचित जातियॉ, जनजातियॉ तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिल पाते हैं जो समाज की तथाकथित अगड़ी जातियों के बच्चों को मिल जाते हैं।

(छ) शारीरिक दोष– विकलांग तथा विभिनन प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कमियों से युक्त बालक–बालिकायें भी अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में समानता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पर्याप्त जोर देने के बावजूद भी अन्धे, लूले, लंगड़े, बहरे, गूॅगे तथा मंदबुद्धि के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था प्रायः नहीं हो पाती है। ये बच्चे समाज के ऊपर बोझ के रूप में बने रहने को विवश हैं जबकि इन्हें उचित शिक्षा व प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।

4. पब्लिक स्कूलों की निरन्तर बढ़ती संख्या और इनके प्रभावी नियंत्रण में कमी– पब्लिक स्कूलों की स्थापना समाज के सभी वर्गो की शिक्षा के साथ–साथ सरकार द्वारा प्रत्येक स्थान पर शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था में कमी को देखते हुए एक सामाजिक योगदान के रूप में की गयी थी जिसका उद्देश्य सरकार के सहयोग, समाज के उत्थान एवं शिक्षा की सर्वसुलभता को लेकर था किन्तु धीरे–धीरे पब्लिक स्कूल उच्च आय वर्ग के बालक–बालिकाओं के शिक्षा के केन्द्र बन गये तथा ये शैक्षिक स्तर पर अभिजात्य वर्ग एवं निम्न वर्ग का एक स्तरीकृत स्वरूप बनाने लगे। पब्लिक स्कूलों में यद्यपि भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता अधिक होती है किन्तु ये इसके बदले में एक मोटा शुल्क वसूल

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-8, No.-II, Issues-IX YEAR- Dec-2017

करते हैं जो जनसामान्य के लिये दुर्लभ होता है।

5. शैक्षिक मानकों में ह्रास– वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में शैक्षिक मानकों में सतत् ह्रास की समस्या एक विशेष चुनौती के रूप में उभरी है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर एवं शिक्षक–शिक्षार्थी, प्रशासक एवं प्रबन्धन हर स्तर पर शैक्षिक मानकों में कमी दिखायी पड़ती है।

6. भाषा समस्या– देश के लिए एक पाठ्यचर्या, समान इच्छा नीति एवं समान शिक्षा व्यवस्था के लिए भाषा सम्बन्धी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न आयोग एवं समितियों के सुझाव के आधार त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया जिसके अनुसार तीन भाषाएँ राजभाषा हिन्दी, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी तथा मातृभाषा या राज्यभाषा को मान्यता प्रदान की गयी किन्तु अनेक राज्यों में मातृभाषा एवं राज्य भाषा के अलग होने तथा हिन्दी के ज्ञान के अभाव में इसका निरन्तर विरोध होता रहा। इसका दुष्परिणाम सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए समान पाठ्यचर्या, एक समान शिक्षण पद्धति एवं लोगों में एकीकरण की भावना विकसित करने की चुनौती विद्यमान है।

7. छात्र आन्दोलन एवं अनुशासनहीनता की समस्या– वर्तमान में यह एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गयी है विद्यार्थियों में निरन्तर गैर अनुशासनिक कार्य एवं आन्दोलन, मारपीट, घेराव, हडताल, तोड़फोड, उद्दण्डता, आगजनी एवं अशान्ति की गतिविधियॉं की जाती हैं जिसके कारण समाज के शैक्षिक व्यवस्था से जुड़े लोग अत्यन्त चिन्तित हैं। छात्रों द्वारा यह अनेक रूपों में सम्पादित की जाती है वे कक्षाकक्षा, विद्यालय परिसर एवं विद्यालय के बाहर ऐसे कृत्य करते हैं जिसके कारण अशान्ति एवं भय का वातावरण उत्पन्न होता है।

8. परीक्षा एवं मूल्यांकन की समस्या– परीक्षा एवं मूल्यांकन विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमता का निर्धारक माना जाता है इसी के आधार पर उन्हें किसी भी कार्य के लिये योग्य मान लिया जाता है। परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन व्यवस्था को शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी बनाने हेतु विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने सुझाव प्रदान किये तथा वर्तमान परीक्षा प्रणाली को उपयोगी नहीं माना गया। वर्तमान परीक्षा प्रणाली आज भी पुरानी पद्धति एवं व्यक्तिनिष्ठ तरीके से सम्पादित की जाती है जिसमें विद्यार्थियों के ज्ञान का एकपक्षीय मूल्यांकन होता है।

9. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में कमी– शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन से विद्यार्थियों की समझ एवं क्षमता की बचत होती है तथा वे विभिन्न परिस्थितियों के साथ सरलता से समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं किन्तु वर्तमान में विद्यार्थियों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में सतत् अभाव दृष्टिगत होता है।

10. शैक्षिक प्रशासन एवं नियोजन की समस्या– वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी अनेक समस्याएँ दृष्टिगत होती हैं जिनमें प्रमुख समस्याएँ निम्नवत हैं–

1. शिक्षा पर नियंत्रण की समस्या।
2. भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की कमी।
3. लालफीताशाही का तेजी से बढ़ता प्रभाव।
4. केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं में परस्पर समन्वय की कमी।
5. शैक्षिक संस्थाओं में जनसहयोग एवं जनभागीदारी की कमी।
6. कार्मिक वर्ग की पर्याप्त संख्या न होना।
7. जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था न हो पाना।
8. दोषपूर्ण शैक्षिक नियोजन की समस्या।
9. शैक्षिक प्रशासकों में उत्तरदयित्व एवं जबाबदेहिता की भावना की कमी।

11. शिक्षित बेरोजगारी की समस्या : शिक्षित बेरोजगारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या है आज देश में लगभग 4 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी फौज है जो विभिन्न नौकरियों एवं व्यवसायों के लिए योग्यता धारित करते हैं किन्तु इनके लिए अवसर न उपलब्ध हो पाने से वे लम्बे समय तक इसके लिये प्रयास करते हैं और अन्त में अपनी योग्यता से निम्न कार्य करने पर मजबूर होते हैं इसका प्रभाव उनकी मनोवृत्ति पर पड़ती है और वे कुण्ठा, निराशा व अवसाद की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं।

निष्कर्ष– इस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं से ग्रस्त है इसमें शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पक्षों की सक्रियता द्वारा इसका निदान किया जाना सम्भव हो सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन्हीं कमियों एवं विसंगतियों के दूर करने हेतु नई विश्वविद्यालीय परीक्षा प्रणाली 2020 का क्रियान्वयन किया है जिसके द्वारा सन् 2022 तक पूरे देश में एकीकृत समन्वित एवं विद्यार्थियों की आवश्यकता, उपयोगिता एवं

सक्षमता आधारित शिक्षा प्रणाली के विकास एवं क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है जिसके द्वारा शिक्षा के स्वरूप, उसकी पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियों, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की स्थिति तथा सामाजिक व सामुदायिक पक्षों को जोड़कर एक उन्नत शैक्षिक व्यवस्था स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाठक, पी0डी0 (2004) भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
2. भारतीय आधुनिक शिक्षा, जनवरी 2002 (राश्ट्रीय पैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिशद)।
3. गुप्ता, एस0पी0 एवं गुप्ता, अलका (2012–13) : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, प्रयागराज।
4. चौबे, सरयू प्रसाद (2002) : भारतीय शिक्षा की चुनौतियाँ : नीति एवं परिप्रेक्ष्य, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।
5. सारस्वत, मालती एवं गौतम, एस0एल0 (2008) : भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।
6. लाल, रमन बिहारी (2014–15) : शिक्षा के दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार, आर0 लाल बुक डिपो, मेरठ।
7. मिश्रा, के0एस0 एवं उपाध्याय, प्रतिभा (1996) : शिक्षा में उदीयमान चुनौतियाँ, लोकहित प्रकाशन, प्रयागराज।

*****